भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1967
दिनांक 31 जुलाई 2025

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी-वन के अंतर्गत परियोजनाएं

1967 **श्री ज्ञानेश्वर पाटील:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के अंतर्गत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए विशेषकर मध्य प्रदेश से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने स्वीकृत किए गए हैं;
(ख) प्रधानमंत्री जी-वन जैव-एथेनॉल परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुमोदित जैव-एथेनॉल परियोजनाओं के लिए आज तक स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) चयनित जैव-एथेनॉल परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है और उनके पूरा होने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;
(घ) जैव-एथेनॉल परियोजनाओं के पूरा होने में कोई देरी हुई है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी देरी की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): सरकार ने, लिग्नोसेल्युलोसिक जैवमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण) योजना" 2019, वर्ष 2024 में यथा संशोधित, को अधिसूचित किया था। इस योजना के तहत कुल 14 वाणिज्यिक पैमाने के प्रस्ताव और 8 प्रदर्शन पैमाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 8 वाणिज्यिक पैमाना परियोजनाओं तथा 5 प्रदर्शन पैमाना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उक्त प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश से नहीं है।

वर्ष 2024 में पीएम जी-वन योजना में संशोधन के बाद, उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की शुरुआत करने में सहायता करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 अगस्त, 2025 को अंतिम तिथि के रूप में रखकर नए प्रस्तावों की मांग की गई। अब तक, मध्य प्रदेश के एक प्रस्ताव सहित 6 प्रस्ताव (3 वाणिज्यिक परियोजनाएं तथा 3 डेमो परियोजनाएं) प्राप्त हुए हैं।

पीएम-जीवन योजना के तहत अनुमोदित जैव-एथेनॉल परियोजना हेतु, अनुमोदित वित्तीय सहायता, वितरित तथा पूरा करने की समयसीमा का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	परियोजना डेवलपर	राज्य	परियोजना प्रकार	अनुमोदन का वर्ष	स्वीकृत वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)	वितरित वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये में)	पूरा होने की समय-सीमा
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा	वाणिज्यिक	2020	150	75	कमीशन किया गया
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ओडिशा	वाणिज्यिक	2020	150	75	कमीशनिंग की जा रही है
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पंजाब	वाणिज्यिक	2020	150	37.5	मार्च, 2026 तक यांत्रिक रूप से पूरा होना
4	नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड	असम	वाणिज्यिक	2020	150	75	कमीशनिंग की जा रही है
5	मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड	कर्नाटक	वाणिज्यिक	2022	100	शून्य	परियोजना-पूर्व कार्यकलाप प्रगति पर हैं
6	राइस सेल्यूलोज प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	वाणिज्यिक	2023	150	शून्य	परियोजना-पूर्व कार्यकलाप प्रगति पर हैं
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा	प्रदर्शन	2020	15	7.5	कमीशनिंग की जा रही है
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिहार	प्रदर्शन	2022	15	शून्य	परियोजना-पूर्व कार्यकलाप प्रगति पर हैं
9	लिग्नोपुरा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	प्रदर्शन	2023	13.25	शून्य	परियोजना-पूर्व कार्यकलाप प्रगति पर हैं
10	गोदावरी बायो-रिफाइनरीज लिमिटेड	कर्नाटक	प्रदर्शन	2023	15	शून्य	परियोजना-पूर्व कार्यकलाप प्रगति पर हैं

कोविड-19 के कारण संयंत्र निर्माण का प्रभावित होना, नई तकनीकी उपकरणों के लिए सीमित विक्रेता, इवेपोरेटर आदि जैसी विशिष्ट वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई समय-सीमा के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई है। सरकार द्वारा परियोजना कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समस्याओं का निरंतर समाधान किया जाता है।

*****